

मध्य प्रदेश शासन

वित्त विभाग

क्रमांक 1038 /4-नि0-2/72 भोपाल, दिनांक 5 जून, 1972

प्रति,

शासन के सप्ले विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व डिवेल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्य प्रदेश ।

विषय:- सामान्य भविष्य निधि में से रकम निकालने के अनुरोध के संबंध में कार्यविधि ।

==0==

प्रवर्तमान कार्य विधि के अनुसार, सामान्य भविष्य निधि नियम, 1955 के नियम 15-3 के अधीन सामान्य निधि में से निकाली जाने वाली रकमों को अनुरोध करने वाले अधिकारियों को औपचारिक अनुरोध जारी कर दिये जाने के बाद संबंधित लेखाधिकारी से अधिकार पत्र प्राप्त होने पर ही निकाली जा सकता है । इस कार्यविधि को कुछ समय से शासन द्वारा सत्रोद्धा के जा रही थी । शासन द्वारा इस विधि को समीक्षा करने के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि रकम निकालने के संबंध में लेखा-अधिकारी का अपेक्षित अधिकार पत्र आवश्यक नहीं साझा जाना चाहिये । उपर्युक्त नियम को लागू करने के लिए नोट 2 को अनुरोध किया गया । जब तक कि रकम निकालने के लिये इच्छुक कोई आवेदनकर्ता, भविष्य निधि लेखे के नवीनतम उपलब्ध विवरण पत्र के आधार पर तथ्या उसके बाद किये गये अंशदानों का प्रमाण लेकर सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा अपनी रकम के बारे में सक्षम अधिकारी का समाधान करने की स्थिति में हो, तो सक्षम अधिकारी निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत स्वयं ही रकम निकालने के अनुरोध प्रदान कर सकता है, जैसा कि वापस किये जाने योग्य पेशगी के मामले में किया जाता है । ऐसा करते समय, सक्षम अधिकारी संबंधित अंशदाता को पहले ही निकालने के लिए अनुरोध करेगा । परन्तु जब आवेदनकर्ता अपने खाते में जमा रकम के बारे में सक्षम अधिकारी का समाधान करने की स्थिति में नहीं हो अर्थात् जब आवेदनकर्ता द्वारा जारी गई रकम के देय होने के बारे में कोई भी संदेह हो तो आवेदनकर्ता के खाते में रकम (रकम) का ठोकठीक पता लगाने के लिये संबंधित लेखा अधिकारी को लिखा जा सकता है । ताकि सक्षम अधिकारी निकाली जाने वाली रकम के देय होने के बारे में निश्चय कर सकें रकम निकालने के स्वीकृत पत्र में सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या तथ्या लेखे रखने

रखने वाले लेखा अधिकारी का उल्लेख स्पष्टतः किया जाना चाहिए तथा उसे सुनिश्चित करके निर्दिष्ट रूप से उसी लेखा अधिकारी को भेजा जाना चाहिए। स्वीकृति प्रदान करने वाला अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि लेखा अधिकारी से इससे पारदर्शी प्राप्त हो गई है और रकम निकालने को अनुरोध को अंशदाता के लेख खाते में नोट कर दिया गया है। यदि लेखा अधिकारी इस आवास के रिपोर्ट दे कि अनुरोध को गई रकम अंशदाता के खाते में नया रकम से अधिक है अथवा अन्यथा देय नहीं है तो उस स्थिति में यह आवश्यक होगा कि अंशदाता निकाली गई पुरी रकम वापस करें।

2. म०प्र०, सामान्यभविष्य नियम नियमावली 1955 के वर्तमान उपाबंधों में संशोधन करने के प्रश्न को अलग से उठाया जा रहा है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

देवीप्रसाद

(देवी प्रसाद)

उप सचिव

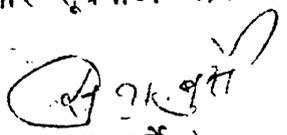
पृष्ठंकन क्रमांक 1059 /4-नि०-2/72 भोपाल, दिनांक 5 जून, 1972

प्रतिलिपि:-

- सचिव/सैनिक सचिव, राज्यपाल महोदय,
- सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश, इन्दौर,
- नियंत्रक, शासन प्रवृत्त एवं लेखन सामग्री, मध्य प्रदेश, भोपाल,
- राज्य सतर्कता आयोग, मध्य प्रदेश, भोपाल,
- पंजीयक/रिपोर्टिंग अधिकारी/लेखा अधिकारी, म०प्र० सचिवालय, भोपाल,
- समस्त, वित्त अधिकारी/लेखा अधिकारी/निष्पालय अधिकारी, म०प्र० के

और सूचनाएँ एवं मार्गदर्शन के लिए अग्रिम।

- 1. /-/-
- 2. महालेखाकार, मध्य प्रदेश, ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनाएँ अर्पित।
- 3. सचिव, विधान सभा सचिवालय, भोपाल की सूचनाएँ अर्पित।
- 4. निबंधक उच्च न्यायालय, म०प्र०, जबलपुर की ओर सूचनाएँ अर्पित।


(सु०ना० दुर्गे)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

वित्त विभाग

===

क्रमांक 1392 / 4 नि.2

भोपाल, दिनांक

15 जुलाई, 1972

प्रति,

शासन के सपरत विभाग,
अधिका, राजस्व बंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त संभारगीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश,

विषय: - सामान्य भविष्य निधियों में से रकम निकालने की संज्ञा के संबंध में कार्य दिष्टि ।

===

शासन के ध्यान में यह बात लाई गई है कि वित्त विभाग के आपन क्रमांक 1058/4 नि.2/72 दिनांक 5 जून, 1972 की अधिका 2 में मध्यप्रदेश कोषालय संहिता भाग 1 के नियम 529(1) में संशोधन किये जाने के संबंध में उल्लेख न किये जाने के कारण कोषालयधिकारी अंशदाताओं का समय अधिकाओं वदारा विकर्षण की स्वीकृति दी जाने के पश्चात भी रकम का भुगतान नहीं करते है ।

अतः वित्त विभाग के उक्त आपन की अधिका के प्रतिलिपि में स्पष्ट किया जाता है कि मध्यप्रदेश सामान्य भविष्य निधि विमानती 1955 तथा म0प्र0 कोषालय संहिता भाग 1 के वर्तमान उपबन्धों में संशोधन करने के प्रश्न को अलग से उठाया जा रहा है ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा

वाकिशायकर,

(सु 10 जुलै)

अवर सचिव

क्रमांक 1393 / 4 नि.2

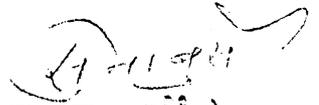
भोपाल, दिनांक

15 जुलाई, 1972

प्रतिलिपि: -

राज्यपाल के सचिव/सैनिक सचिव, मध्यप्रदेश, भोपाल,
सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर,
निष्पत्रक, शासकीय मुद्रणालय, मध्यप्रदेश, भोपाल,
सतर्करा आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल,
एंग्लो-इण्डियन/रक्षासहायिका/ लेखा अधिकारी, मध्यप्रदेश कोषालय,
भोपाल,
समस्त वित्तीय अधिकारी/लेखाधिकारी/कोषालय अधिकारी को भोपाल
जुलाई प्रेषित है ।

2. महालेखाकार, प्रयागप्रदेश, जबलपुर/भोपाल को ओर सूचनाएं प्रेषित है ।
3. जतिव, विधान सभा सचिवालय, प्रयागप्रदेश, भोपाल को ओर सूचनाएं प्रेषित है ।
4. निबंधक, प्रयागप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को ओर सूचनाएं ।


(सु० ना० बु०)

अवर सचिव,
प्रयागप्रदेश शासन, वित्त विभाग

परिहार/ *